भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2270 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

जल मेट्रो प्रणालियों का विस्तार

†2270. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोच्चि जल मेट्रो के अनुरूप आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल जल आधारित सार्वजनिक परिवहन गलियारों का विस्तार करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति के प्रारूप के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देशव्यापी, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितने नौगम्य शहरी जलमार्गों की पहचान की गई है, व्यवहार्यता अध्ययन के लिए शहरों को मंजूरी दी गई है और पर्यावरण के अनुकूल विद्युत नौकाओं को चालू किया गया है;

(ग) अपनाए गए शून्य-उत्सर्जन तकनीकी ढांचे का संरचनात्मक ब्यौरा क्या है जिसमें हाइब्रिड प्रणोदन जलयानों के लिए मानकीकरण आवश्यकताएं, फास्ट चार्जिंग अवसंरचना और सड़क और रेल नेटवर्क के साथ मल्टीमॉडल एकीकरण शामिल हैं; और

(घ) सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसी व्यवहार्य वित्तपोषण संरचनाओं को स्थापित करने, पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को रोकने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क), (ग) और (घ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय योजना, कार्यान्वयन, सुरक्षा मानदंड को बढ़ावा देने और पर्यावरण-अनुकूल जल-आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल मेट्रो दिशानिर्देश, 2026 को तैयार कर रहा हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत शून्य/कम-उत्सर्जन तकनीकी रूपरेखा, मानकीकरण अपेक्षाओं, वित्तपोषण संरचनाओं, पर्यावरण सुरक्षा और अंतर-मंत्रालयी समन्वय से संबन्धित पहलुओं को शामिल किया गया हैं।

(ख): भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्लूएआई), पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय ने देश में 18 निर्धारित स्थानों पर शहरी जल मेट्रो प्रणालियों के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया हैं। 15 स्थानों का व्यवहार्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया हैं जो जल-आधारित शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी व्यवहार्यता, अवसंरचना आवश्यकताओं, परिचालन रूपरेखा, और संभावना का आकलन करने में सहायता करेगा। हालांकि, चार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पोतों को वाराणसी, अयोध्या, पटना और कोलकता में तैनात किया गया है; और मंत्रालय की अन्य पहलों के तहत वाराणसी में एक हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत तैनात किया गया हैं।

*****